

9

10

43

प्रेषक

विस्तारयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी।
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा।

यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III(2)

दिनांक: 18-12-91

विषय- विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण बारे।

राज्य सरकार ने राजकीय विद्यालय भवनों की सौजन्य दशा तथा बढ़ती हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी मरम्मत इत्यादि तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण हेतु एक योजना बद्ध कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा अतिरिक्त कमरों के निर्माण का कार्य सम्बन्धित उपायुक्त की देख रेख में युद्ध स्तर पर किया जाना है और जिला के उपायुक्त द्वारा इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी अपनी मासिक बैठक में की जानी है।

1. जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे राजकीय विद्यालय भवनों की सूची (i) जिनके भवन मरकादा तथा अक्षुब्ध हैं तथा जिनमें मरम्मत की निताम्त आवश्यकता है अथवा (ii) जिन विद्यालयों में अतिरिक्त भेरी कमरों का निर्माण करवाया जाना है, उन पर चर्चा होने वाली अनुमानित राशि तथा विद्यालय की विभिन्न-विभिन्न छात्र विधियों में दिनांक 31-12-91 तक उपलब्ध राशि दर्शाते हुए सम्बन्धित उपायुक्त को उपलब्ध करायेंगे।

2. जिला स्तर पर राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरों का निर्माण का कार्य करवाने के लिये निम्नानुसार विकास योजनाओं में राशि का प्रावधान है :-

1. अवाहुर रोडगार योजना के अन्तर्गत विद्यालयों में नए कमरों का निर्माण
2. विकेंद्रित योजना स्क्रीम के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत।
3. मैचिंग ग्रांट के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा कमरों का निर्माण।
4. हरियाणा प्राथमिक विकास फंड की योजना के अन्तर्गत नए कमरों का निर्माण।

3. शिक्षा विभाग के बजट में आवंटित राशि तथा पिछले स्तर पर एकत्रित भवन-विधि पूरा भनी से विद्यालय भवनों की मरम्मत/कमरों का निर्माण।

अवाहुर रोडगार योजना तथा हरियाणा प्राथमिक विकास फंड की राशि को जोड़ कर जिन स्कूलों की राशि को विद्यालय स्तर पर एकत्रित भवन विधि पूरा भनी में कम करवाया जाय। सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को सूचित किया जायेगा कि जिला विकास फंड की राशि से अवाहुर रोडगार योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवनों की मरम्मत/कमरों का निर्माण ही करवाया जायेगा।

3. प्रत्येक जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में उपरोक्त कार्य हेतु एक समिति का गठन किया जाए। यह समिति जिला शिक्षा अधिकारी के सहयोग से विद्यालय भवनों की स्थिति की समीक्षा करेगी तथा विद्यालय भवनों के कार्य की प्राथमिकता प्रत्येक जिला वर्ष के प्रथम मास अर्थात् 30 फरवरी तक उपलब्ध राशि को सम्मुख रखते हुए इतर मार्गिक करेगी जिसकी एक प्रति निदेशक सिकेबरी शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा को भी भेजेगी। वित्तीय वर्ष 1991-92 के केवल तीन महीने शेष हैं इसलिये कथित समिति द्वारा तीन महीनों का ही कार्यक्रम दिनांक 15-1-92 तक तैयार किया जाए तथा उसकी प्रति निदेशक सिकेबरी शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा को भेजी जाए। प्राथमिकता निर्धारित करते समय पहले उन विद्यालय भवनों के मरम्मत के कार्य टेकअप किए जाएं, जिनके भवन असुरक्षित हैं तथा जिनमें अभियंता घटना होने का अंदेशा बना रहता है। कमरों का निर्माण करते समय सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालयों में भोजी कक्षों की आवश्यकताओं को पूरा करवाया जाए तदोपरान्त माध्यमिक/उच्च एवं बरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में भोजी कक्षों के निर्माण बारे कार्यवाही की जाए। अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तर पर गठित की जाने वाली समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. उप मण्डल अधिकारी (नगरिक)
2. कार्यकारी अभियन्ता (पंचायती राज)
3. जिला शिक्षा अधिकारी/जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
4. जिला के सभी उप मध्यम शिक्षा अधिकारी।

4. विद्यालय भवनों की मरम्मत/कमरों के निर्माण के कार्यों के अनुपात सम्बन्धित -जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा "सिंगल फाईल" पर अतिरिक्त उपायुक्त को प्रकाशकीय/वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे। तदोपरान्त कार्य विद्यालय स्तर पर पर गठित की गई निर्माण समितियों द्वारा सम्पन्न किए जाएंगे। राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत तथा कमरों के निर्माण कार्यों को उन पर सौंपे होने वाली अनुमानित राशि को सम्मुख रखते हुए चार भागों में विभाजित किया जाएगा है -

(क) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी मरम्मत/निर्माण पर 50 हजार रुपये तक की राशि खर्च होने की सम्भावना है, उन विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण का कार्य भवन निधि तियमावली 1989 के अन्तर्गत गठित की गई समिति द्वारा ही करवाया जाएगा।

(ख) ऐसे राजकीय विद्यालय भवन, जिनकी मरम्मत/निर्माण पर 50 हजार रुपये से अधिक तथा एक लाख रुपये तक की राशि खर्च होने का अनुमान है, उन विद्यालयों में समिति गठित करके कार्य सम्पन्न करवाया जाए। इस समिति का गठन निम्नानुसार किया जाय -

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. विद्यालय का सम्बन्धित मुख्याध्यक्ष/प्रधानाचार्य | समिति का अध्यक्ष/अकादमिक आफिसर |
| 2. ब्लॉक का भोवरडीयर (पंचायती राज) | टेक्नीकल सदस्य |
| 3. सम्बन्धित विद्यालय के डी.पी.ओ का प्रधान/सदस्य | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित ग्राम का सरपंच तथा व.अ.स. सदस्य | सदस्य |
| 5. सम्बन्धित विद्यालय में कार्यरत कोई बरिष्ठ अध्यापक | सदस्य |

इस प्रकार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु गठित की जाने वाली समिति का अध्यक्ष सम्बन्धित उप मण्डल शिक्षा अधिकारी तथा अकादमिक आफिसर, सम्बन्धित विद्यालय का मुखिया होगा तथा प्राथमिक विद्यालय के किये गये समितियों का अध्यक्ष सम्बन्धित अर्थ-शिक्षा अधिकारी और अकादमिक आफिसर सम्बन्धित विद्यालय का हीव टीचर होगा। कमरों के अन्य सदस्य उपरोक्त अनुसार ही होंगे।

(ग) ऐसे विद्यालय, जिनके भवनों पर एक लाख रुपये से अधिक राशि खर्च होने का अनुमान है, के कार्य को सम्पन्न करवाने हेतु उन मण्डल अधिकारी (नगरिक) की अध्यक्षता में समिति का गठन

SDEO

DEO

One copy

SDO/SDM

6
42
45

One Lac to Five Lacs

किया जाए, जिसके अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. एस० डी० घो० (पंचायती राज)
2. सम्बन्धित उप मण्डल शिक्षा अधिकारी
3. सम्बन्धित ग्राम पंचायत का सरपंच तथा मंत्री पंचायत
4. सम्बन्धित विद्यालय के पी० टी० ए० के प्रधान/सदस्य
5. सम्बन्धित स्कूल का मुखिया

टेक्नीकल सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
अकाउंटिंग ऑफिसर

(ब) ऐसे विद्यालय भवन जिमकी मरम्मत/निर्माण पर 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक की राशि बच होने का अनुमान है, के कार्यों को जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित करके कार्य को सम्पन्न करवाया जाएगा। इस समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे -

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. कार्यकारी अभियन्ता (पंचायती राज)
3. संबंधित ग्राम का सरपंच तथा मंत्री पंचायत
4. संबंधित विद्यालय का मुखिया

सदस्य
टेक्नीकल सदस्य
सदस्य
अकाउंटिंग ऑफिसर

नोट - जहाँ तक में स्थित विद्यालयों के मामले में ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सदस्य के स्थान पर म्यूजिसिपल कमिटी का प्रधान तथा सदस्य को शामिल किया जाए।

5. उपरोक्त परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि जब तक हरियाणा राज्य के सभी राजकीय विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक शिक्षा विभाग के बजट में इन कार्यों के लिये व्यवस्थित राशि (तान प्लान/प्लान) में से कोष निर्माण विभाग को केवल इस समय चल रहे कार्य पूरे भवनों का निर्माण तथा 10 लाख रुपये से अधिक राशि के मरम्मत के कार्यों को सम्पन्न करने हेतु ही दी जाए।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके असा० क्रमांक 3793-3802-3 वि० वि० 11-91/ दिनांक 29-11-91 द्वारा दी गई संख्या अनुसार जारी की गई है।

हस्ता/-
(स० डी० गुप्ता)
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग

दिनांक 19-12-91

स० क्रमांक 23/42/91- वि० III (2)

एक प्रति महासेवाकार हरियाणा (i) (ए एण्ड ई) (ii) अतिरिक्त जहाँ तक की सुचनाएँ भेजी जाती है।

हस्ता/-
उप सचिव, शिक्षा,
उत्तरे वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा, सरकार,
शिक्षा विभाग।

दिनांक 19-12-91

स० क्रमांक 23/42/91- वि० III (2)

ADC

5 Lacs to 10 Lacs

पू० क्रमांक 2/43-2006

दिनांक 31-1-2007

एक-एक प्रति प्रति शिक्षा आयुक्त निदेशक सकेन्द्रीय शिक्षा / निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग।

पू० क्रमांक 2/43-2006

दिनांक 31-1-2007

एक-एक प्रति प्रधान सचिव / विशेष कार्य अधिकारी / निजी सचिव, मुख्यमंत्री तथा कनिष्ठ सचिव / सचिव / निजी सचिव / मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण / मुख्य संसदीय सचिव को सूचनार्थ भेजी जाती है।

उप सचिव, शिक्षा,
कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग।

एक प्रति सभी वित्तायुक्तों / आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप सचिव, शिक्षा,
कृते वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग।

संकेत में,

सभी वित्तायुक्तों / आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार

क्रमांक 2/43-2006 वृत्त (2)

दिनांक 31-1-2007

(2)

46

एक-एक प्रति निदेशक उच्चतर शिक्षा/निदेशक सहायक शिक्षा/निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, चण्डीगढ़ तथा निदेशक पंचायत विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तार्युक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

सं० क्रमांक 23/42/91-सि० III (2)

दिनांक 19-12-91

एक-एक प्रति प्रधान सचिव/उप प्रधान सचिव/विशेष कार्य अधिकारी/निज सचिव, मुख्य मन्त्री तथा वरिष्ठ सचिव/सचिव/निज सचिव/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण मुख्य संसदीय सचिव को सूचनाएं भेजी जाती हैं :

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तार्युक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

एक प्रति सभी विस्तार्युक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार को सूचनाएं भेजित है ।

हस्ता/-

उप सचिव, शिक्षा,

कृते: विस्तार्युक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शिक्षा विभाग ।

सेवा में

सभी विस्तार्युक्तों/आयुक्तों एवं सचिवों, हरियाणा सरकार

सं० क्रमांक 23/42/91- सि० III (2)

दिनांक 19-12-91

(8) (43) 47

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

सेवा में

1. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त
2. हरियाणा के सभी जिला शिक्षा अधिकारी/ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. सभी जिला पंचायत तथा विकास अधिकारी, हरियाणा ।

यादी क्रमांक 2/43-2006 वर्क्स (2)
दिनांक, चण्डीगढ़ । 31-1-2007

विषय : विद्यालय भवनों की मरम्मत/निर्माण बारे ।

उपरोक्त विषय पर सरकार के पत्र क्रमांक 43/42/91 शि-III (2) दिनांक 19.12.1981
की निरन्तरता में ।

अंकित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों के पैरा 4 (क), (ख), (ग) और (घ) में
राशि के खर्च की सीमा निम्न अनुसार बढ़ाई जाती है :-

- (क) 50 हजार रुपये से 1.00 लाख रुपये तक ।
- (ख) 1.00 लाख रुपये से अधिक तथा 5.00 लाख रुपये तक ।
- (ग) 5.00 लाख रुपये से अधिक तथा 10.00 लाख रुपये तक ।
- (घ) 10.00 लाख रुपये से अधिक तथा 20.00 लाख रुपये तक ।

शेष दिशा निर्देश यथावत रहेंगे ।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा उनके आदेश क्रमांक 60/119/07-03 वि. शिक्षा-II /
108 दिनांक 30/1/2007 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की गई है ।

उप प्रधान सचिव

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।

पू 0 क्रमांक 2/43-2006 वर्क्स (2)

दिनांक 31-1-2007

एक प्रति महालेखाकार हरियाणा (1) (ए एम्ड डी) (11) अडिटेड चण्डीगढ़ को सूचना भेजी जाती है ।

उप प्रधान सचिव, शिक्षा,

कृते: वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव हरियाणा सरकार
शिक्षा विभाग ।